भाजपा और उसके जोटीदारों को अगले चुनावों में पटखनी दो

CITU Library

सीटू प्रकाशन

मार्च 2004

मूल्य दो रुपये

वाजपेयी की सरकार की विदेश नीति का झुकाव साम्राज्यवाद की ओर रहा; उसके दौर में बदतरीन किसम के दंगे हुए; कानून की धज्जियां उड़ते देखी गई; खूनी हिंसा का तांडव होते देखा गया; रिकार्डतोड़ घोटाले हुए जिनमें एनडीए के मंत्री तथा नेता शामिल पाए गए; इस शासन ने अपने वोट बैंक को और पुख्ता करने के लिये 'हिन्दुत्व' का पत्ता खुल कर खेला है और उसके लिये आक्रमक तेवर अपनाने से भी यह शासन बाज नहीं आया; यही नहीं, इस सरकार के दौर में जन साधारण के जनवादी अधिकारों पर भी पूरी ताकत के साथ धावा बोला गया।

सत्ता के लिये मानवीय मूल्यों की बली चढ़ाई जाती रही

भाजपा के शासन काल में यही होना था और यही हुआ भी। उसकी आर्थिक नीति बड़े जगीरदारों तथा पूंजीवादी ताकतों की सेवा करने वाली थी; इनमें देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के लोग हैं; दूसरी ओर जनता की विशाल बहुसंख्या को इसका आर्थिक बोझ अपने कंधों पर ढोने के लिये मजबूर होना पड़ा है। वर्ष 1998–2003 के बीच पेश किये गए प्रत्येक वार्षिक बजट तथा 2004 के चुनाव पूर्व अंतरिम बजट में पूंजीपतियों तथा सामंतों एवं भूमिपतियों की श्रेणी को दिल खोल कर मालामाल किया गया है; करों में छूटों, अनुदानों, संस्थागत समझौतों तथा दूसरे कई तरह के आड़े तिरछे ढंग तरीकों से उन्हें भारी भरकम आर्थिक लाभ पहुंचाए गए; इसके बदले में गरीब जनता को क्या मिला? उनके कंधों पर करों, ऊंचे मूल्यों का अधिक से अधिक भारी भरकम बोझ डालने के मामले में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी गई; कारखाना बंदी, रोजगारों की क्षति तथा कई और ढंग तरीके अपना कर उन्हें हाल से बदहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। ऐसी घोर जन विरोधी आर्थिक नीतियों जो धनवानों के लिये वरदान से कम नहीं कही जा सकतीं, के खिलाफ जन साधारण में पनप रहे भारी असंतोष को शांत करने के लिये भी भाजपा के भोंपुओं ने बड़े नायाब ढंग तरीके अपना रखे हैं; यह सब सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है; इसके लिये घिनावने हथकण्डे अपनाए जा रहे हैं; मानवीय जीवन के मूल्यों की बलि चढ़ाई जा रही है; फिरकावाराना फसाद कराने के लिये जमीन तैयार की जा रही है; मतदाताओं को आपस में लड़ाने और उनमें फूट डालने के लिये कोई भी हथकण्डा अपनाने से उन्हें गुरेज नहीं नहीं किया जा रहा; महज इसलिये कि वे हकूमत में बने रहें। गुजरात के दंगों तथा उनसे पहले गोधरा में जो दिल दहला देने वाला नर संहार हुआ था, उनके पीछे संघ परिवार के संगठनों का हाथ दिखाई देता है; ये जघन्य कांड महज इसलिये कराए गए ताकि वे लोग गुजरात में अपना शासन जारी रख सकें तथा इसकी सहायता से दूसरे राज्यों में भी सत्ता की डोर उनके हाथों में खिंची चली आए।

घोटालेबाजों तथा ठग्गों की सरकार

भाजपा लोगों को धोखा देकर ही केन्द्र में सत्तारूढ़ हो सकी थी; इसके लिये उसने लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाना बेहतर समझा था। इन्हीं चालबाजियों तथा फिरकापरस्ती की गंदी खेल के सहारे ये लोग पांच साल तक अपनी हकूमत को बनाए रख सके। अब क्योंकि आगामी चुनाव सिर पर हैं इसलिये वे फिर से लोगों की आंखों में धूल पर धूल झोंकते चले जा रहे हैं; अपने प्रचार अभियान में झूठ का सहारा ले रहे हैं; साम्प्रदायिक उन्माद को बढ़ाया जा रहा है ताकि वे किसी न किसी प्रकार एक बार फिर से राजनीतिक सत्ता को हथिया सकें।

पिछले पांच वर्षों के 'सुशासन' ने उनके घिनावने चेहरे को बेनकाब कर दिया है; वे देश तथा देश की जनता के दुश्मन साबित हुए हैं। उनकी आर्थिक नीतियां देश के आत्म निर्भर विकास के मोल पर साम्राज्यवादियों के हाथों में देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को गिरवी रखने वाली हैं।

पिछले पचास वर्षों में जो राष्ट्रीय दौलत अथवा परिसम्पित्तियां बनाई गई थीं, उन्हें पागलपन की सीमा तक जाकर निजीकरण का अभियान चला कर कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। और इस प्रक्रिया में देश के वसीह कुदरती वसीलों तथा अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाओं एवं जन उपयोगी सुविधाओं को निजी क्षेत्र देशी तथा विदेशी, दोनों की झोली में डाला जा रहा है।

यहीं पर बस नहीं, निजीकरण का प्रत्येक मामला भ्रष्टाचार के कीचड़ से लथपथ है; परिसम्पत्तियों की दृष्टि से समृद्ध सार्वजनिक इकाईयों को बेच डालने की प्रक्रिया कुछ इस ढंग से चलाई गई कि ये परिसम्पत्तियां लगभग मुफ्त में ही खरीदने वाले की झोली में चली गईं। इसके चलते देश के राजकोष को जबरदस्त क्षति हुई है; इसमें लाभ किसे हुआ; जाहिर है इसका लाभ उठाने वाले लोगों में निजी क्षेत्र के खरीददार, सौदे करने के काम में लगे अधिकारी तथा मंत्रिगण इत्यादि शामिल हैं। निजीकरण के मामलों में भ्रष्टाचार की यह दास्तान केवल मेज के नीचे से लेन देन करने की नहीं है बल्कि ये काम परिसम्पत्तियों तथा शेयरों का मूल्य बहुत ही कम लगाने के संस्थागत समझौतों के जरिये सुव्यवस्थित ढंग से किये गए। भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने घोटालों की इस दौड़ में चैम्पियन बन कर अपना नाम खूब 'रौशन' किया है; एनडीए मंत्रिमण्डल के कई सदस्य रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए; किकबैक्स तथा प्रतिरक्षा उपकरणों की खरीद के मामले में जम कर भ्रष्टाचार हुआ है। कभी स्टाक मार्किट का घोटाला हुआ, कभी कारगिल कफन घोटाला, तहलका कांड, स्टैम्प–पेपर घोटाला, विदेशी मुद्रा के लेन देन का घोटाला और ऐसे ही अनेक घोटाले एक के बाद एक होते चले गए; इन बड़े–बड़े घोटालों के आगे राजीव गांधी के शासन काल में बोफोर्स तोपों की

खरीद का घोटाला भी फीका पड़ गया है। भाजपा शासन के ये सभी घोटाले सीधे तौर पर मंत्रियों की निगहबानी में हुए हैं।

ठग्गी अब भी जारी है...

चुनाव आ जाने पर एनडीए के भोपुओं ने हमलावरी तेवर अपनाते हुए प्रचार माध्यमों प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक दोनों में ही झूठ का तूफान खड़ा कर दिया; राष्ट्रीय राजकोष में से सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर दिये गए; दूसरे शब्दों में करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिये गए। ये लोग झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं; उन सब की बात करना यहां सम्भव नहीं है फिर भी उनमें से कुछेक का विश्लेषण तो किया ही जा सकता है।

आम लोगों की कीमत पर अमीरों को मालामाल किया गया

गैर कृषि उत्पादों, सैल फोन, कोयला, कुछ उपकरणों तथा हिस्से पुर्जों पर सीमा शुल्क की ऊपरी दरों में कटौती; लेप टाप कम्पयूटर सामान के साथ विदेश से लाने की अनुमति दिये जाने; विदेशी शराब के डयूटी फ्री आयात की अनुमत्य सीमा को बढ़ाए जाने; हवाई सफर के लिये देश के भीतर तथा विदेश यात्रा करने से सम्बन्धित करों में जबरदस्त कटौती किये जाने; हवाबाजी में काम आने वाले ईंधन पर आबकारी शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती करना इत्यादि काम वाजपेयी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहे हैं जो जनवरी 2004 में पेश किये गए अंतरिम बजट में भी प्रतिबिम्बित होते हैं। मुशकिल से दस प्रतिशत लोगों को इन कदमों से लाभ होगा जबकि जन साधारण की विशाल श्रेणियों को तो इनका भारी भरकम बोझ अपने कंधों पर ढोना होगा। देश के राजकोष को भी जबरदस्त क्षति झेलनी पड़ेगी; उसे मार्च 2004 तक लगभग 11000 करोड़ रुपये का चूना लग ही चुका था।

लोगों की विशाल संख्या के लिये सार्वजनिक उपभोग की शानदार योजनाएं तो हैं पर धन का नामो निशान दिखाई नहीं देता

वित्त मंत्री महोदय ने 50,000 करोड़ रुपये की "कृषि सम्बन्धी अंदरूनी ढांचा कोष" तथा 50,000 करोड़ रुपये की ही एक और "लघु एवं मंझौले उद्योगों सम्बन्धी कोष" जैसी बहुत ही शानदार योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। किन्तु ये घोषणाएं केवल सार्वजनिक उपभोग के लिये हैं; वोट हासिल करने के लिये लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इन योजनाओं के लिये एक लाख रुपये जुटाने का वादा तो किया गया है पर असल में पूरे वित्तीय वर्ष के लिये केवल 2000 करोड़ रुपये की मामूली रकम ही रखी गई है।

इस धोखे का नाम है सामाजिक सुरक्षा

इलेक्ट्रानिक मीडिया हर रोज वाजपेयी को एक नेता की मुद्रा में दिखाता है; वह ''असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 37 करोड़ श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की योजना शुरू कर रहे हैं।'' कहा तो यह जा रहा है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को सेवा निवृत्त होने के बाद 500 रुपये की मासिक पेन्शन को यकीनी बनाया जाएगा; इसके अलावा 1,25,000 रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। इस झूठ का भी कोई जवाब नहीं है।

वाजपेयी सरकार के अंतरिम बजट में इस योजना के लिये एक पैसा भी नहीं रखा गया; यद्यपि सरकार से सामाजिक सुरक्षा के लिये उक्त संचित कोष के लिये प्रति श्रमिक न्यूनतम वेतन के 1.16 प्रतिशत भाग का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। यह लिखित योजना तथा सरकार की ओर से 23 जनवरी, 2004 को जारी किये गए वक्तव्य में बताया गया है कि यह योजना अगले पांच वर्षों की अवधि के लिये होगी; इसे देश के गिने चुने 50 जिलों में लागू किया जाएगा; यह केवल 25 लाख श्रमिकों के लिये होगी——यह संख्या '37 करोड़' के सबसे छोटे भाग के बराबर भी नहीं है। मीडिया में चलाए जा रहे प्रचार अभियान के समय ये तथ्य जनता को नहीं बताए जाते क्योंकि तथ्य तो तथ्य ही होते हैं; वे लोगों को धोखा नहीं दे सकते और न ही उन्हें गुमराह कर सकते हैं।

•

8 प्रतिशत विकास दर की कपोल कल्पना

चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर लगभग 8 प्रतिशत रहेगी, इस बारे में बड़ी बड़ी डींगे हांकी जा रही हैं। वाजपेयी सरकार निश्चित रूप में इसका श्रेय ले सकती है; इसलिये नहीं कि उसके दौर में असल अर्थों में उच्चतर आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहीं की जा सकी बल्कि इसलिये कि उसने झूठ मूठ के आंकड़ों की जादूगरी करके यह कमाल भी करके दिखा दिया। उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि पिछले वर्ष औद्योगिक मंदे तथा सूखा प्रभावित वर्ष में कृषि में गिरावट होने के चलते वृद्धि दर असामान्य रूप में सबसे कम रही थी। क्योंकि पिछले वर्ष की विकास दर बहुत कम थी इसलिये उसके आधार पर इस वर्ष की ऊंची विकास दर से उसकी तुलना करके यह उछल कूद मचाई जा रही है। ये महानुभाव एक और जादूगरी भी कर रहे हैं; इस वर्ष की 'ऊंची' विकास दर का यश गान करने तथा लोगों को सब्जबाग दिखाने के लिये वे पहले से ही घोषित पिछले वर्ष की कम विकास दर 4.8 प्रतिशत में अधोगामी संशोधन करते चले जा रहे है; पहले उसे कम करके 4.3 प्रतिशत दिखाया गया और बाद में और कमी करके उसे 4 प्रतिशत दिखाया गया। इस चुनावी वर्ष

में उन्होंने 8 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पिछले पांच वर्षों में वार्षिक आनुपातिक वृद्धि दर पर एक दृष्टि डालने से लोगो को पता चल जाएगा कि एनडीए सरकार के दौर में अर्थ व्यवस्था की स्थिति कैसी रही। आर्थिक सर्वेक्षणों तथा रिजर्व बैंक की ओर से प्रकाशित आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि:

1. वर्ष 2003 तक नयी सहस्राब्दि के तीनों वर्षों में वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 1990 के दशक की आनुपातिक वृद्धि दर से कहीं कम रही है; इसका अर्थ है उदारीकरण की नयी सत्ता के पहले दशक ने अर्थ व्यवस्था की गाड़ी को उस रास्ते पर धकेल दिया जो गिरावट की ओर जाता है।

2. एनडीए शासन काल से पहले की अवधि मे आनुपातिक वार्षिक वृद्धि दर 6.7प्रतिशत थी उसकी तुलना में 1998–2003 की अवधि में और एनडीए शासन काल में 5 प्रतिशत से भी नीचे चली गई है।

84 लाख रोजगार पैदा करने का मिथक

प्रधान मंत्री ने इससे पहले एक घोंषणा करके वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त एक करोड़ रोजगार जुटाए जाएंगे। ज्यों ज्यों चुनाव निकट आते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसका अधिक से अधिक श्रेय ले रहे हैं; उन्होंने दावा किया है कि पिछले वर्ष 84 लाख नये रोजगार पैदा किये गए। उन्होंने एक बार फिर झूठ बोलने की सभी सीमाएं तोड़ दीं।

संगठित क्षेत्र का रोजगार पिछले पांच वर्षों से लगातार कम होता चला जा रहा है। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने संसद में स्वीकार किया था कि 31 मार्च, 2002 को खत्म होने वाले वर्ष में 4.2 लाख रोजगारों में और गिरावट दर्ज की गई; इस प्रकार लगातार पांचवें वर्ष रोजगारों में गिरावट आई है। 1996–97 तथा 2001–02 के बीच इन पूरे पांच वर्षों में संगठित क्षेत्र के लगभग 8.8 लाख रोजगार पर कुल्हाड़ी चल चुकी थी। रोजगार परिदृश्य का एक विश्लेषण दर्शाता है कि 5.1 प्रतिशत तक सर्वाधिक कमी खनन एवं उत्खनन के क्षेत्र में दर्ज की गई; उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। मार्च 2001 को समाप्त तिमाही में रोजगार वृद्धि का अंचल वार विश्लेषण करें तो पता चल जाएगा कि मार्च 2000 को समाप्त उससे पिछली तिमाही की तुलना में सबसे अधिक 3.01 प्रतिशत की गिरावट केन्द्रीय अंचल में आई; उसके बाद पश्चिम अंचल में 1.06 प्रतिशत की गिरावट आई तथा उत्तरी अंचल में 0.84 प्रतिशत की गिरावट आई थी। राज्यों तथा केन्द्रीय शासित प्रदेशों के विश्लेषण से प्रतिबिम्बित होता है कि केवल पांडिचेरि, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में 3 प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज की गई।

रोजगार में सबसे अधिक गिरावट (3.59) अर्ध सरकारी (केन्द्रीय) क्षेत्र

में दर्ज की गई; उसके बाद राज्य सरकारी, अर्ध सरकारी (राज्य), तथा केन्द्रीय सरकार का नम्बर आता है जिनमें क्रमशः 0.47 प्रतिशत, 0.41 प्रतिशत तथा 0.38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (बिजनस स्टैंडर्ड, 17 मई, 2003)। केन्द्रीय सरकार ने क्योंकि अगले पांच वर्षो में 10 प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक वर्ष 66000 रोजगारों की दर से रोजगारों में कमी लाने का फैसला किया है; उसके अनुरूप सरकारी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की हालत पहले ही नकारात्मक बन गई है।

संगठित क्षेत्र में रोजगारों में कमी आने का यह रुझान लगातार चल रहा है। पिछले वर्ष अर्थात् 2003 में डाक विभाग में 10,000 पद समाप्त कर दिये गए; इस वक्त की सरकार चाहती है कि इस विभाग में काम करने वाले तीन लाख से अधिक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या में एक लाख तक की कमी कर दी जाए। रेलवे में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' कोटियों में 30–11–2003 को 1.57 लाख पद रिक्त पड़े थे; उन्हें अभी तक भरा नहीं गया है ताकि आउट–सोर्सिंग तथा भविष्य में किये जाने वाले नैगमकरण तथा निजीकरण के लिये अनुकूल· स्थितियां पैदा की जा सकें। आयकर विभाग व्यापक स्तर पर आउटसोर्सिंग से काम ले रहा है; इसके फलस्वरूप उसके 55,000 कर्मचारियों में से 30,000 कर्मचारी अतिरिक्त हो गए हैं। ज्यालोजिकल सर्वेक्षण के प्रमुख कामों जैसे जमीन के नीचे कोयले तथा समुद्र में तेल के भण्डारों का पता लगाना; को कम किया जा रहा है, इसके चलते उसके 4500 कर्मचारी अतिरिक्त हो गए हैं। राष्ट्रीय बचत संगठन को भंग करके उसके 1100 कर्मचारियों के रोजगार पर लात मार दी गई है। भारत सरकार की ओर से कोलकाता में स्थित विकास आयुक्त लौह एवं इस्पात के कार्यालय एवं भण्डार, सहायक निदेशक आपूर्ति विभाग के कार्यालय को एकदम बंद कर देने के आदेश जारी कर दिये हैं। भारत सरकार के स्टेशनरी विभाग के कार्यालय को सितम्बर 2004 तक बंद कर दिया जाएगा; इस कार्यालय में लगभग 800 कर्मचारियों काम करते हैं। ताजा समाचारों के अनुसार मार्च 2004 तक चार राष्ट्रीयकृत जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों में काम करने वाले लगभग 8000 कर्मचारियों के रोजगार पर कुल्हाड़ी चलने वाली है; आर्थिक दैनिकों के अनुसार यह कुल्हाड़ी स्वेच्छिक सेवा निवशत्ति योजना के माध्यम से चलाई जाएगी (द इकनामिक टाइम्स, 02–03–2004)।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि सरकार ने 84 लाख रोजगार पैदा किये हैं तो कहां किये हैं। असंगठित क्षेत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नये रोजगारों का सृजन हुआ है; वर्तमान सरकार का दावा तो यही है।

सूचना प्रोद्योगिकी की वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है कि उसमें इतनी बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन हो सके। टाटा इकनामिक सर्विसिज़ से

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002 के अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का रोजगार लगभग सात लाख था, जो कुल रोजगार के एक बहुत छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर लोग घरेलू अर्थ व्यवस्था के लिये नहीं बल्कि बिजनस प्रोसैस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) के रास्ते दूसरे देशों के लिये काम कर रहे हैं। यह रास्ता सदा बना रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं क्योंकि इस रास्ते से काम कराने वाले देशों में बीपीओ का विरोध बढ़ता चला जा रहा है। यही नहीं, देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग तथा आपूर्ति पर कराए गए एक अध्ययन में लगाए गए अनुमानों के अनुसार अगले चार वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कुल आपूर्ति 11.68 लाख तक पहुंच जाएगी जबकि इसी अवधि में आइटी से सम्बन्धित रोजगार में लगभग 11.20 लाख की बढ़ोतरी होगी। इसके चलते अकेले आइटी क्षेत्र में लगभग 48000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे (इंडियन एक्सप्रेस, 27–2–2004) आइटी रोजगारों में बढ़ोतरी होने की बातें इस अवधारणा के आधार पर की जा रही हैं कि दूसरे देशों से आउटसोर्सिंग का मौजूदा रुझान बिना किसी रुकावट के बना रहेगा; यह अवधारणा यर्थाथपरक कतई नहीं है। जब तक आर्थिक नीति को बदला नहीं जाता और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भीतर संगठित उत्पादनकारी उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक आइटी क्षेत्र में भी बेरोजगारी की तीव्रता के रुझान को रोका नहीं जा सकेगा; उस हालत में इस क्षेत्र की स्थिति भी बद से बदतर होती चली जाएगी। भाजपा की अगुवाई वाली मौजूदा सत्ता अपनी औद्योगिक नीति को बदलने की इच्छा नहीं रखती।

असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के सृजन की असल तस्वीर कतई उज्जवल नहीं है; जैसा कि दावा किया जा रहा है। कृषि, खनन एवं उत्खनन तथा निर्माण ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें असंगठित क्षेत्र का सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध होता है। वर्ष 2001–02 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि तथा उत्खनन दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार में क्रमवार 50 लाख तथा 4.3 लाख की कुल गिरावट हुई थी। उस अवधि में निर्माण क्षेत्र के रोजगार में लगभग 51 लाख की बढ़ोतरी हुई थी। इसलिये ये तीनों क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रोजगार के प्रमुख भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब को मिला कर देखा जाए तो हमें रोजगार सृजन के मामले में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी।

संक्षेप में, एनडीए सरकार के दौर में संगठित क्षेत्र के रोजगार में पूरी गिरावट देखने को मिली है। रोजगार वृद्धि का पिछले पांच वर्षों का रुझान भी यही दर्शाता है कि असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार वृद्धि बेहद कम रही। एनडीए सरकार का यह दावा कि 2003 में 84 लाख नये रोजगारों का सृजन

हुआ था, निराधार है!

जब आर्थिक नीति ही रोजगार हीन विकास करने की हो और देश की अर्थ व्यवस्था की मैन्युफैक्चरिंग की स्वदेशी व्यवस्था का क्षरण करने वाली हो तब व्यापक स्तर पर रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है? डब्ल्यूटीओ के निदेशों से भी आगे जाकर आयातों का अंधाधुंध उदारीकरण किया जा रहा है, आयात शुल्कों में कमी लाई जा रही है और इसके विपरीत आबकारी शुल्कों को न्यूनाधिक अपरिवर्तित रखा जा रहा है; इसके चलते देश के मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पर कहर टूट पड़ा है। भाजपा की आर्थिक नीति की दिशा सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को विनाश के गड्ढे में धकेल देने वाली है। यही कारण है कि बैंकों में निवेश योग्य धन की बाढ़ लाए जाने पर भी स्वदेशी निवेशों की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आती चली जा रही है; इसके साथ ही ब्याज की ऊंची तथा पक्षपाती दरों के चलते किसान को ऋण उपलब्ध नहीं हो रहे। गोदाम अनाज से भरे होने पर भी लोग भूखों मर रहे हैं।

इस हालत में जब "श्रम शक्ति का आकार कम किये जाने" तथा "संविदाकरण" की नीति सरकार के लिये अर्थ व्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाने की रणनीति बन चुकी हो ताकि लागतों में कमी की जा सके; तो उससे केवल निजी क्षेत्र को ही तालाबंदियों के माध्यम से श्रम लागत में कमी करने, गैर कानूनी ढंग से कामबंदी करने, श्रमिकों की छंटनी करने तथा सभी श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाने के लिये ही प्रोत्साहन मिलता है। इस हालत में रोजगार का सृजन हो ही नहीं सकता और रोजगार की वृद्धि दर में गिरावट होना अवश्यंभावी हो जाता है। पढ़े लिखे बेरोजगारों में रोजगार की हालत बद से बदतर हो जाएगी और यह संकट और अधिक गहरा हो जाएगा। कोई झूठा व्यक्ति ही रोजगारों में बढ़ोतरी होने की डींग हांक सकता है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिये मगरमच्छ के आंसू

ग्रामीण विकास खर्चों के क्षेत्र जिसमें रोजगार सृजन, विशेष क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि सभी कार्यक्रम शामिल हैं, के मामले में एनडीए सरकार की कारगुजारी कैसी रही; इस सम्बन्ध में उपलब्ध तथ्य कौन सी कहानी कहते हैं? यह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में लगातार डकैती डालने और गांवों के लोगों को सकल घरेलू उत्पाद में उनके बनते भाग से उन्हें वंचित किये जाने की दुखभरी कहानी है। ग्रामीण विकास व्यय 1985–90 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 14.5 प्रतिशत था जो 1990 के दशक के शुरूआती वर्षों में गिर कर 8 प्रतिशत रह गया; 1998 तक पहुंचते पहुंचते वह और कम हो गया अर्थात् 6 प्रतिशत रह गया। उसके बाद के वर्षों में यह गिर कर 5 प्रतिशत रह गया है। इसका अर्थ है, "सुधार शुरू होने से पहले के वर्षों की तुलना में ग्रामीण विकास व्यय 30,000 करोड़

रुपये वार्षिक की आनुपातिक कमी हुई है'' इसका अर्थ यह है कि हमारी कृषि आय में 20000 करोड़ रुपये से लेकर 1,50,000 करोड़ रुपये के बीच कमी हुई है—यह जबरदस्त कमी है, इसमें संदेह नहीं।

उपरोक्त स्थिति के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कृषि में सकल पूंजी के गठन में निरंतर कमी आती चली गई है; बड़े सामंतों को हर प्रकार की सुविधाएं एवं छूटें दिये जाने तथा उदारीकरण के सभी कदम उठाए जाने पर भी वर्ष 2001—02 में यह महज 1.3 प्रतिशत रह गई थी। कृषि क्षेत्र के रोजगार वार्षिक वृद्धि दर जो 1983—93 में 1.51 प्रतिशत थी वर्ष 1993—2000 के बीच नीचे सरकती हुई महज –0.34 प्रतिशत पर अटक गई थी। गिरावट का यह रुझान मौजूदा वर्ष में भी चल रहा है। खेतिहर श्रमिकों को वर्ष में मुशकिल से 100 दिनों के लिये काम मिलता है और इस पर भी सरकार के रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों में इन्हें रोजगार प्राप्त लोग माना जाता है जबकि ये श्रमिक देहात की कामकाजी जनता की विशाल बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही साथ भूमिहीन परिवारों अथवा घरों की प्रतिशतता में भी बढ़ोतरी हुई है; वर्ष 1987—88 में इनकी कुल प्रतिशतता 35 प्रतिशत थी जो 1999—2000 में बढ़ कर 41 प्रतिशत हो गई है।

एनडीए के महारथियों ने विज्ञापनों के माध्यम से दावा किया है कि उनके शासनकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 56 प्रतिशत कर दिया गया। किन्तु जब सरकारी खरीद की प्रक्रिया सुस्त हो जाए और कृषि में काम आने वाली सामग्री के दाम यदा कदा बढ़ते चले जाएं तो समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का अर्थ रह ही क्या जाता है; इन महानुभावों ने बड़ी बेशर्मी से काम लेते हुए इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की है। उर्वरकों (खाद) के मूल्यों में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो चुकी है। डीज़ल और महंगा हो गया है; उसके मूल्यों में 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है और मिट्टी के तेल के दाम तो तीन गुणा से भी अधिक बढ़ चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में बिजली, सिंचाई तथा बीज इत्यादि के मूल्यों में शत प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कृषकों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले मंझौले तथा सीमांतक किसानों के मामले में ये लागतें कमर तोड़ देने वाली हैं। ये सेवाएं प्रदान करने के बदले में बड़े सामंतों की ओर से भारी भरकम पैसे वसूल किये जाते हैं। सरकार की ओर से एमएसपी में जो तथाकथित बढ़ोतरी की गई है, उसका बड़ा हिस्सा तो यही लोग लूट कर ले जाते हैं।

भूखे गरीबों के लिये खाना

प्रधानमंत्री ने बड़े जोरशोर से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) को और व्यापक बनाने की घोषणा की थी; उन्होंने कहा था कि गांवों में रहने वाले

और 50 लाख गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा; वर्तमान में 150 लाख गांवों में रहने वाले भूखे लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। उन्हें सीमित मात्रा में चावल 2 रुपये प्रति किलो तथा गेहूं 3 रुपये प्रति किलो की दर से सुलभ कराया जाता है।

इस योजना के लिये केवल 2000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। जहां 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों वहां इतनी अल्प राशि का आबंटन करना और वह भी केवल छोटी सी संख्या के लिये अर्थहीन होकर रह जाता है; क्या इसका कोई तुक है?

अनाजों की प्रति व्यक्ति खपत 1997–98 में 174.2 किलोग्राम प्रति वर्ष थी; सूखे से पहले के वर्ष 2000–01 में यह खपत कम होकर केवल 151.06 किलोग्राम रह गई थी; सूखे के बाद के वर्ष 2002–03 में यह खपत 156.55 किलोग्राम रही अर्थात् उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण लोगों को कम से कम कितनी कैलोरी नसीब होती हैं, यदि आप यह जानने का प्रयास करेंगे तो आपको हालत बहुत शोचनीय दिखाई देंगे। खुराक के मामले में 66.6 प्रतिशत से अधिक देहाती लोगों की हालत पोषण की दृष्टि से बेहद खराब है। खाद्य सुरक्षा पर खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूखे पेट सोने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है; 1995–97 में भूखे लोगों की संख्या 19.40 करोड़ थी जो 1999–2001 में बढ़ कर 21.45 करोड़ हो गई। एक अनुमान के अनुसार पिछले पांच वर्षों में कम से कम 16000 किसानों की ओर से आत्महत्याएं की गई हैं।

अन्तयोजय अन्न योजना के लिये भले ही अत्यंत अल्प राशि का आबंटन किया गया है किन्तु वह भी तो जनता के लक्ष्य समूह तक पहुंच नहीं पाती। देश के अधिकांश राज्यों में ग्रामीण समाज के प्रबंधन की स्थिति ऐसी ही है। इस योजना को लागू करने वाले अभिकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा उचित मूल्य दर की दुकानें हैं। ये अभिकरण काम कैसे करते हैं, इसके बारे में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है; वह भी उस सरकार के अन्तर्गत जिसका उद्देश्य ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विनाश करना हो।

ग्रामीण विकास के बारे में राष्ट्रीय संस्थान (एनआइआरडी) की ओर से कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की कुल संख्या के लिये आबंटित चावल के 20–25 प्रतिशत भाग और गरीबी की रेखा के ऊपर के राशन कार्ड धारकों के लिये

आबंटित चावल के 50 प्रतिशत भाग को उचित मूल्य दर की दुकानों के स्तर पर ही किसी दूसरे काम में लगा दिया गया; दूसरे शब्दों में उस पर हाथ साफ कर लिया गया। अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी के रेखा

के नीचे रहने वाले लोगों के लिये आबंटित गेहूं के 50 प्रतिशत भाग को किसी और 'काम' में लगा दिया गया। महाराष्ट्र में भी 50 प्रतिशत से अधिक आबंटित गेहूं इन लोगों के पास पहुंचा ही नहीं था। (बिजनस लाइन, 04–02–2003)।

खाद्य सब्सिडी देने के उद्देश्य से 27000 करोड़ रुपये खर्च किये गए हैं; यह दावा इस वक्त की सरकार की ओर से चीख–चीख कर किया जा रहा है। इसकी असल कहानी क्या है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव जिन्होंने 1997 में खाद्य मंत्री के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये लक्ष्य का निर्धारण किया था, ने कहा, "27000 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का पैंसठ प्रतिशत भाग नौकरशाहों के वेतनों का भुगतान करने, प्रतिष्ठान के खर्चों की भरपाई करने, भण्डारण, व्यापारियों तथा निर्यातकों पर खर्च करने के काम आ गया। बाकी बचा 35 प्रतिशत किसी और काम से खर्च हो गया या दूसरे ढंगों से उस पर हाथ साफ कर लिया गया।" (टाइम्स आफ इंडिया, 31–12–2003) एक गैर सरकारी संगठन 'परिवर्तन' की ओर से पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों पर एक सर्वेक्षण कराया गया था; उस सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक अनाज उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं जो अत्याधिक गरीब हैं। 'परिवर्तन' की ओर पूर्वी दिल्ली के सीलम पुर इलाके के नजदीक वैलकम कालोनी में जाकर 160 परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि "एक भी परिवार को पूरी मात्रा में अनाज नहीं मिला। केवल 23 प्रतिशत लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिला; वह भी निर्धारित मात्रा से कम था और उसके लिये अधिक दाम वसूल किये गए।" (टाइम्स आफ इंडिया, 31–12–2003)

इस अंत्योदय योजना का आने वाले समय में क्या हाल होने जा रहा है? इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। कहने को तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो चावल तथा 3 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है पर उसका बहुत बड़ा भाग इन लोगों तक पहुंचता ही नहीं; यह उपहार इन गरीब लोगों के घरों में जाने की बजाए बेशर्म व्यापारियों की जेबों में चला जाता है; ये महानुभाव सब्सिडी वाले इस अनाज को खुले बाजार में 10 रुपये प्रति किलो और या फिर विदेशी बाजार में 5 रुपये प्रति किलो बेच कर अपनी जेबें लबालब भरते चले जा रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के घरों में जाने के स्थान पर यह अनाज कहीं और अर्थात् व्यापारियों की दुकानों में चला गया। बीपीएल के ये पत्ते धन्ना सेठों के यहां गिरवी रखे जा चुके हैं। अधिकांश राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है। इसका खुशनुमा अहसास निश्चित तौर पर व्यापारियों तथा उचित मूल्य दर दुकानों के मालिकों को ही होगा; वे लोग ही एनडीए सरकार की घोषणाओं का स्वागत करेंगे, जन साधारण नहीं

जबकि ये योजनाएं उसी के लिये बनाई गई थीं। ये घोषणाएं अमल करने के लिये नहीं बनाई गई बल्कि मच्छली (वोट) पकड़ने के लिये बनाई जाती हैं!

''भारत उज्जवल'' अथवा ''फील गुड'' पर किसके लिये?

भाजपा की ओर से विज्ञापनों जरिये एक जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया जा रहा है; विज्ञापनों में प्रधानमंत्री तथा दूसरे नेताओं की आदमकद तस्वीर छापी जाती है; तथाकथित "फील गुड" अथवा "भारत उज्जवल" का अभियान चला कर पूरे देश में एनडीए के हक में माहौल बनाया जा रहा है। जन साधारण को फील गुड जैसा कोई कारक अथवा भारत उज्जवल कहीं दिखाई नहीं देता... ... आखिरकार पिछले दो वर्षो में मानव विकास सूचकांक के मामले में 175 देशों की सूची में भारत का स्थान और नीचे सरक गया है; पहले उसका स्थान 123वां होता था पर अब और नीचे सरक कर 127वां हो गया है। क्या इसे भारत उज्जवल कहा जाता है?

खुशनुमा अहसास किन लोगों को होता है; फील गुड कारक किसे दिखाई देता है; इसका दावा करने वाले महानुभाव कौन हैं? ये लोग हैं लालकृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारती! इन लोगों पर फौजदारी मामला चल रहा है; इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं इस पर भी ये लोग भारत में सत्ता के मीठे फलों का सवाद चख रहे हैं; उन्हें तो खुशनुमा अहसास होगा ही। जार्ज फर्नाडिस रिश्वत कांड में शामिल पाए गए; तहलका टेप में उनकी पोल खोली गई; कफन घोटाले में भी उनका नाम लिया गया; इस पर भी श्रीमान जी देश के प्रतिरक्षा मंत्री के पद को सुशोभित करते चले जा रहे हैं; वह एक संतुष्ट व्यक्ति हैं; उन्हें फील गुड क्यों नहीं होगा? तेलगी घोटाले के कीचड़ के छींटे जिन पुलिस अधिकारियों की वर्दियों तथा विधायकों की अचकनों पर पड़े थे; वे भी तो लोगों की आंखों में धूल झोंक कर 60,000 करोड़ रुपये के मीठे फलों का सवाद चख रहे हैं; उन्हें भी तो फील गुड होगा! निजी क्षेत्र की बड़ी मछलियां जिनकी झोंली में कौड़ियों के दाम सार्वजनिक क्षेत्र की बहुमूल्य परिसम्पत्तियां डाल दी गई हैं उनका दिल भी तो बाग बाग हो गया होगा! प्रधानमंत्री कार्यालय के वे लोग जिन्हें यूटीआइ घोटाले से लाभ मिला और उन पांच मंत्रियों जिनके खिलाफ केन्द्रीय स्तर्कता आयोग ने प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दी थी, को भी तो फील गुड होगा; उसके कारण भी हैं। सार्वजनिक बैंकों के 1,20,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के नैगम घरानों की करतूतों के चलते बट्टेखाते चले गए हैं; इन्हीं महापुरुषों की ओर से 1.50 लाख करोड़ रुपये के करों तथा दूसरी देनदारियों का भुगतान करने की जरूरत ही महसूस नहीं की; अब यदि इन लोगों को खुशनुमा अहसास नहीं होगा तो और किसे होगा? उन्हें इस समय सचमुच में

ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। फील गुड के प्रभा मण्डल में सीआइआइ, फिक्की तथा मालिकों की लाबी का होना स्वाभाविक ही है क्योंकि उनके दोनों हाथों में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने लड्डू जो थमा दिये हैं; श्रम कानूनों में तबदीली लाकर सरकार ने उनके लिये श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाना सरल बना दिया है और उसका प्रशासन भी सुनियोजित ढंग से कठोर एवं उग्र हो चुका है। तमिलनाडु की घटना इसकी ज्वलंत उदाहरण है।

श्रमिक वर्ग की हालत बद से बदतर हुई

एनडीए के शासन काल में श्रमिक वर्ग के साथ बहुत क़ठोर व्यवहार किया गया। उनके अधिकारों तथा आजीविका को एक के बाद एक होने वाले सुनियोजित हमलों का निशाना बनाया गया। एक ओर तो सरकार की ओर से श्रम कानूनों में बदलाव लाने के लिये जोर शोर से कार्रवाई की गई; उसने "हायर एण्ड फायर" की सत्ता को लागू कर दी तथा पूर्ण संविदाकरण को कानूनी जामा पहना दिया और इस प्रकार श्रमिकों को गुलामी जैसी हालतों में धकेल दिया गया है। क्योंकि श्रमिक आंदोलन के ओर से जोरदार प्रतिरोध किये जाने के कारण भाजपा की अगुवाई वाली सरकार इन विधायी तबदीलियों के लिये संसद में विधेयक ही नहीं ला सकी इसलिये उसने हड़बड़ी में आदेश जारी करके "निर्धारित अवधि के रोजगार" की एक नयी व्यवस्था ही लागू कर दी है जिसके अन्तर्गत सेवा योजकों अथवा मालिकों की श्रेणी को उस अवधि की समाप्ति पर अपने श्रमिकों को काम से निकाल बाहर करने का लाइसेंस ही मिल गया है; उनके इस अधिकार पर कोई अंकुश नहीं होगा। इसके साथ ही साथ निजी क्षेत्र के सेवा योजकों अथवा मालिकों की ओर से न्यूनतम कानूनी औपचारिकताएं पूरी किये बिना ही अंधाधुंध तालाबंदियां की जा रही हैं और इस मामले में एनडीए सरकार बढ़ चढ़ कर उन्हें अपना सहयोग दे रही है। वर्ष 1999 में हड़तालों के कारण जितने मानव दिवसों की क्षति हुई थी उससे कहीं अधिक मानव दिवसों की क्षति गैर कानूनी तालाबंदियों के कारण हुई है; विशेष तौर पर हड़ताल की बजाए तालाबंदियों के कारण आठ गुणा अधिक मानव दिवसों की क्षति हुई है। उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल करने के श्रमिकों के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करते समय सेवा योजकों की श्रेणी की इस परले दर्जे की उद्दण्डता की अनदेखी कर दी। यह शर्म की बात है।

बचतों पर ब्याज दरों में कटौती

इसी सत्ता के समय श्रमिकों पर हमले किये गए, उन्हें हर तरह से लूटा गया। श्रमिकों ने भविष्य निधि के लिये जीवन भर जो बचतें की थीं, उनकी ब्याज दरों में लगातार कटौती की जा रही है। यह कम ब्याज दरों की

सत्ता के नाम पर किया जा रहा है। पहले ये दरें 12 प्रतिशत थीं और कम होते होते आज की तिथि में 9 प्रतिशत रह गई हैं (सरकारी कर्मचारियों के लिये 8 प्रतिशत) और 1 अप्रैल, 2004 से उन्हें और कम करके 8 प्रतिशत तक लाया जाएगा। यदि एनडीए की यह जुंडली सत्ता में बनी रहती है तो न केवल भविष्य निधि बल्कि राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र जैसी सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों में और कमी की जाएगी और आने वाले वर्षों में श्रमिकों की लूट में तेजी आ जाएगी। उल्लेखनीय है कि श्रमिकों तथा कर्मचारियों द्वारा ही इन बचत योजनाओं में भाग लिया जाता है; ब्याज दरों में कटौती होते चले जाने के परिणामस्वरूप उन्हें जबरदस्त आर्थिक हानि झेलनी पड़ रही है। उन्हें अपना धन स्टाक मार्किट में लगाने के लिये मजबूर किया जा रहा है ताकि व्यापारियों की लाबी को बढ़ावा दिया जा सके और वे श्रमिकों की गाढ़े खून पसीने की कमाई से जुआ खेल सकें। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का एक और तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है; उनकी पेन्शन योजना में नित नयी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं; नये प्रवेशार्थियों के लिये यह योजना अंशदायी बनाई जा रही है।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते को वेतन में विलीन कर देने के बारे में सबसे नयी घोषणा की गई है; यह घोषणा इस लिये नहीं की गई कि एनडीए सरकार कर्मचारियों के लिये उदार हो गई है बल्कि उसे अपनी चुनावी मजबूरियों के कारण यह घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा है। उसकी नीतियों के खिलाफ कर्मचारियों में जो असंतोष पनप रहा है वह 24 फरवरी की हड़ताल की तैयारियों के सिलसिले में कर्मचारियों की गतिविधियों से प्रतिबिम्बित हो गया था। इसी एनडीए मंत्रिमण्डल की ओर से लिये गए फैसले के अनुसार केन्द्रीय सरकार के वित्त सचिव ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलीन करने की कर्मचारियों की मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया था। यह मांग कुछ मास पूर्व संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) के सदस्यों की ओर से की गई थी जो कार्रवाई रजिस्टर में दर्ज है। यही नहीं, महंगाई भत्ते को मूल वेतन मे विलीन करने सम्बन्धी एनडीए सरकार की घोषणा उसके पिछले अपराधों के काले धब्बों को धो नहीं सकती; वह श्रम शक्ति का आकार कम करने, दफ्तरों तथा प्रतिष्ठानों की कामबंदी, अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करने और बहुमूल्य सार्वजनिक परिसम्पत्तियां लाभ के भूखे निजी क्षेत्र के मगरमच्छों देशी तथा विदेशी दोनों, की झोली में डालने की अंधाधुंध मुहिम चला कर विशेष तौर पर कर्मचारियों तथा सामान्य रूप में जन साधारण के प्रति यह अपराध तो लगातार करती चली जा रही है।

सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण तथा श्रम शक्ति का आकार कम करने की अंधी मुहिम

इस संदर्भ में एक बात जरूर स्पष्ट हो जानी चाहिये। इस समय की सरकार यह आधार बना कर कि सरकारी विभागों में अतिरिक्त मानव शक्ति है, श्रम शक्ति के आकार को कम करने की अपनी कार्रवाई को उचित करार दे रही है। उसने भयानक ढंग से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। सरकारी सेवाओं में श्रम शक्ति कम करने की अंधी मुहिम सार्वजनिक उपयोग की इन सेवाओं को निजी क्षेत्र के लोगों की झोली में डाल देने के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिये जहां तक मानव शक्ति का सम्बन्ध है, दूसरे देशों की तुलना में भारत में सार्वजनिक सेवाओं में लगे लोगों की संख्या सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से अमरीका में सरकारी कर्मचारियों का अनुपात प्रति हजार 6 से अधिक है; युरोपीय देशों में यह अब भी अधिक है; यहां तक कि विकासशील देशों में भी यह अनुपात जनसंख्या के प्रति हजार चार से अधिक है। भारत में सार्वजनिक कर्मचारियों का यह अनुपात मुशकिल से जनसंख्या के प्रति हजार दो है। एनडीए सरकार कर्मचारी विरोधी है; जन विरोधी है; यह स्थिति उसके इस घिनावने चेहरे को बेनकाब करती है।

संघ परिवार के संगठनों की दोहरी चाल

इसलिये लोगों को धोखा देने और चालबाजियों का सहारा लेकर फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिये भाजपा के भोंपू झूठ और कपट से भरा प्रचार अभियान चला रहे हैं। ज्यों ज्यों चुनाव की तिथियां निकट आती चली जा रही हैं वे देश में साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिये भी दिन रात एक कर रहे हैं। विश्व हिन्दु परिषद तथा बजरंग दल जैसे संघ परिवार के संगठन बढ़-चढ़ कर साम्प्रदायिक नारे लगा रहे हैं; वे अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण करने की पागलपन भरी मुहिम फिर से शुरू कर रहे हैं; इसके लिये घृणा तथा नफरत का माहौल बना रहे हैं। जहां वे तथाकथित हिन्दुत्व को लेकर अपनी उद्दण्डता का प्रदर्शन कर रहे हैं वहां उनका राजनीतिक मुखौटा खुद उदार होने का स्वांग कर रहा है। ये सभी कार्रवाईयां लोगों को धोखा देने, उनमें गलतफहमियां पैदा करने तथा चुनावों में वोट पाने के लिये की जा रही हैं। आर्थिक नीति के मामलों में भी स्वदेशी जागरण मंच तथा भारतीय मजदूर संघ जैसे आर एस एस के घटक संगठन यही दोहरी चाल चल रहे हैं। लोगों के बीच तो वे उदारीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की आर्थिक नीति के खिलाफ जहर उगलते हैं किन्तु जब उन नीतियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने का समय आता है तो ये संगठन पीछे हट जाते हैं।

इन धोखेबाजों को बेनकाब करो,
इनकी हार यकीनी बनाओ

भाजपा की अगुवाई वाला यह गठबंधन एक बार फिर से लोगों को धोखा दे, श्रमिक वर्ग तथा देश के मेहनतकश अवाम को इसकी इजाजत कतई नहीं देनी चाहिये। यह उनके सबसे भयानक शत्रुओं की सत्ता है; इसे सबक सिखाया जाना चाहिये; यह सबक आगामी लोक सभा चुनावों में उसे कड़ी शिकस्त देकर सिखाया जा सकता है। सीआइटीयू मेहनतकश अवाम से अपील करता है कि वह आने वाले समय में सभी धर्म निरपेक्ष तथा जनवादी ताकतों के साथ मिल कर एक शक्तिशाली प्रचार अभियान चलाए; लोगों को भाजपा गठबंधन की राष्ट्र विरोधी तथा जन विरोधी भूमिका की जानकारी दी जाए और बताया जाए कि यह गठबंधन किस प्रकार देश की अर्थ व्यवस्था, पूरे समाज तथा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का बंटाधार कर रहा है; उसे विनाश की गहरी खाई में धकेल रहा है; आगामी चुनावों में उसे धूल चटाने में कोई कोर कसर बाकी न रहने दी जाए।

☛ इस चुनावी जंग में भाजपा को हराओ; भारत की धर्म निरपेक्षता तथा उसकी बहुमूल्य जनवादी परम्पराओं की हिफाजत करो!

☛ वामपक्षी, जनवादी तथा धर्म निरपेक्ष ताकतों को वोट दो ताकि धर्म निरपेक्ष ताकतों की वोट बंटने न पाए!

☛ भाजपा धोखे भरे कट्टड़पंथी नारे लगा कर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है; इस बुराई को सिर उठाने से पहले ही खत्म कर दो; साम्राज्यवाद तथा बहुराष्ट्रीय निगमों से देश को बचाओ!

☛ आगामी चुनावों में भाजपा तथा उसके जोटीदारों को हराने से ही भारत की आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था में चमक पैदा होगी!